

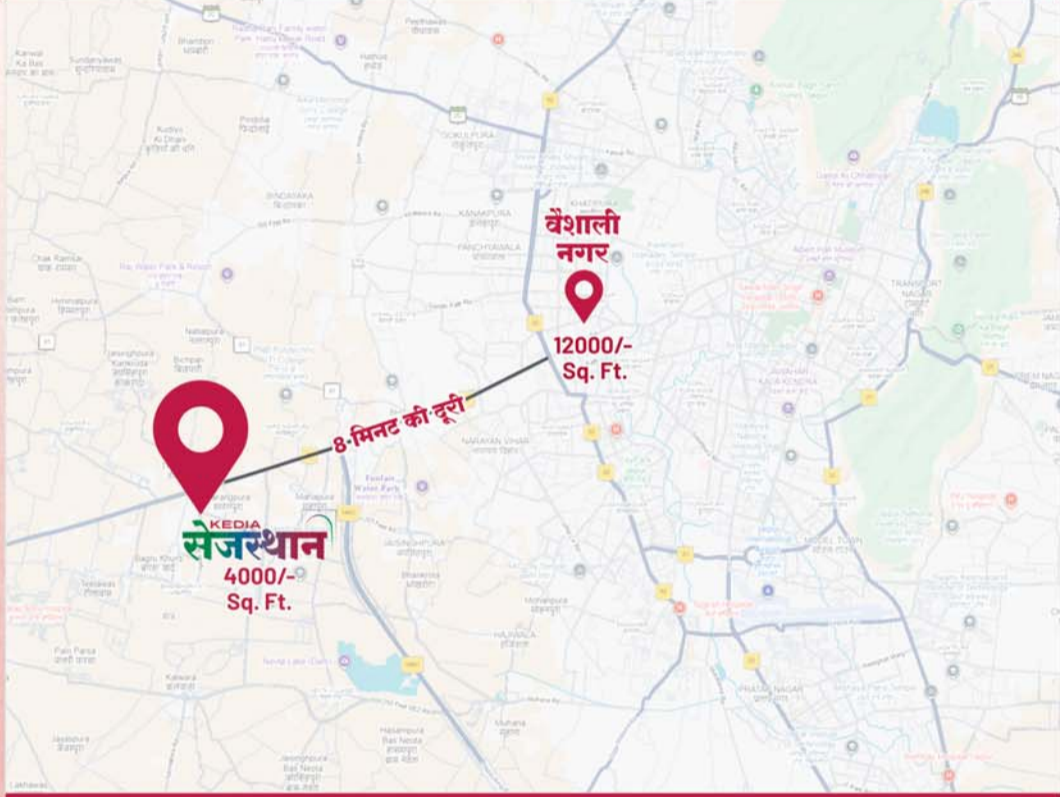


8 मिनट की दूरी पर
8000/- का फायदा
Sq. Ft.

₹4000/-
में फ्लैट!

₹5000/-
में कोठी!

REAL VALUE • REAL GROWTH



अब हर महीने रेट बढ़ेगी!

FIXED PRICE

PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	FIXED PRICE
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	65 LACS
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	75 LACS
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	80 LACS
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.05 CRORE
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.25 CRORE
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.55 CRORE



अजमेर रोड़, जयपुर
बड़ी-बड़ी कोठी, बड़े-बड़े फ्लैट



KEDIA

1800-120-2323
78770-72737

info@kedia.com
www.kedia.com

SCAN QR FOR
• LOCATION
• ROUTE MAP
• SITE 360 TOUR
• E-BROCHURE
• WALKTHROUGH



घर के लिए

घर के खाने के लिए

आन्दोलन
अशुद्ध के विरुद्ध

54000+ रिटेलर्स

पवित्र खिला रहे है

आप कब से खिलाओगे ?

रिटेलर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर
कॉल लगाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ

1800 120 2727

KEDIA™
Pavitra

FIXED PRICE



प्रोडक्ट केटेगरी

आटा और गेहूँ
देशी गेहूँ
शरबती गेहूँ
देशी चक्की आटा
शरबती सुपीरियर आटा
सूजी (सेमोलिना)
गेहूँ दलिया
बेसन
दालें
अरहर दाल
चना दाल
हरा चना
हरा मटर

हरा मूंग (साबुत)
काबुली चना
काला चना
मसूर दाल (लाल)
मसूर मलका
मूंग दाल (छिलका)
मूंग दाल
मोठ
रेड राजमा
राजमा चित्रा
राजमा करमीरी
उड़द दाल (छिलका)
उड़द दाल

मिनी सोया चंक्स
पिसे मसाले
लाकाड्रोग हल्दी पाउडर
लाल मिर्च पाउडर
धनिया पाउडर
सेंधा नमक
अमचूर पाउडर
खड़े मसाले
अजवाइन
काली मिर्च
दालचीनी
लौंग
हरी इलायची

जीरा
कसूरी मेथी
मेथी दाना
राई
सोंफ
धनिया साबुत
डाई फ्रूट
कैलिफोर्निया बादाम
मामरा बादाम
अंजीर
काजू
मूंगफली
मखाना

मेजडूल खजूर
पिस्ता
किरामिथ
अखरोट गिरी
ब्लैडेड मसाले
छाछ मसाला
चना मसाला
चाट मसाला
दाल मखनी मसाला
गरम मसाला
त्रलजीरा मसाला
किचन किंग मसाला
पाव भाजी मसाला

पोहा मसाला
रायता मसाला
राजमा मसाला
सजी मसाला
सांभर मसाला
शाही पनीर मसाला
रनौक्स
चीज़ एंड हर्ब्स मखाना
हिमालयन पिक सॉल्ट मखाना
मैजिक मसाला मखाना
सॉर क्रिम एंड ऑनियन मखाना
रोस्टेड चना

स्वीटनर
देसी गुड़
देसी गुड़ पाउडर
मिश्री धागा
मिश्री पाउडर
एडिबल ऑइल
मूंगफली तेल
पोहा
इंदोरी पोहे
चावल
एलीट बासमती चावल
प्लैटिनम शरबती चावल

40+
Warehouses

180+
Delivery Van

400+
Delivery Man

सभी जिला मुख्यालयों पर Market Development Officer (MDO) हेतु आवेदन करें।
Email ID : hr@kedia.com | Call : +91 76888 44466



विचार बिन्दु

बुद्धि से विचार कर किए गए कर्म ही सफल होते हैं। -महाभारत

राम जल सेतु: राजस्थान की जल स्वावलम्बन क्रांति

राम जल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो सूखे की मार झेलते पूर्वी राजस्थान को जल आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकेल है। यह महज एक इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार की दूरदर्शिता का प्रतीक है, जो संशोधित पार्वती कालीसिंध-चंबल (ERCP) योजना को ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) से जोड़कर एक व्यापक जल मिशन का रूप दे रही है। कल्पना कीजिए, जहां कालीसिंध नदी के उदग्र जल को चंबल नदी के विशाल जलसेतु के माध्यम से मेज नदी ईसरदा बांध, बीसलपुर बांध और अंततः रामगढ़ बांध तक पहुंचाया जा रहा है। इससे 17 जिलों को 3.25 करोड़ जनसंख्या को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों के लिए स्थायी समाधान मिलेगा। यह परियोजना न केवल जल संकट को दूर करेगी, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी। राजस्थान, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान वाला राज्य है, सदियों से जल की कमी से जूझता रहा है। पूर्वी राजस्थान के जिले जैसे कोटा, बूंदी, टोंक, सर्वाई माधोपुर, जयपुर, धौलपुर, करीली, दासा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि में मानसून की अनिच्छा ने किसानों को बाढ़ कर दिया है। फसलें सूखी, तालाब खाली हुए, और भूजल स्तर इतना नीचे चला गया कि हाथ-पंजल हुए ऐसी स्थिति में राम जल सेतु का निर्माण एक श्वनिल परियोजना के रूप में उभरा है। पेंकेज-2 के तहत 2330 करोड़ रुपये की लागत से पीपलदा समेल (कोटा) से गुहाटा (बूंदी) तक देश का सबसे लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। यह संरचना, जो मई 2025 से तेजी से बन रही है, अप्रैल 2026 तक उल्लेखनीय प्रगति पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने हाल में इसका निरीक्षण कर अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर यह 90,000 करोड़ की महायोजना है, जो चंबल बेसिन से बनास, बाणगंगा और अन्य बेसिनों तक जल का समान वितरण सुनिश्चित करेगी।

इस परियोजना की महत्ता को समझने के लिए हमें इतिहास की ओर झांकना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के महासपने को आज साकार करने का समय आ गया है। राम जल सेतु उसी दिशा में एक कदम है। यह वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान और हर घर जल योजना का मजबूत आधार बनेगा। पूर्वी राजस्थान, जहां 40 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वहां अब जल सुरक्षा की बयार बहेगी। ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक जल पहुंचने से जयपुर जैसे महानगरों को भी राहत मिलेगी। किसान नई फसलें उगाएंगे, उद्योग फलेंगे-फूलेंगे, और पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। उदाहरणस्वरूप, कोटा का चंबल उद्यान और बूंदी के किले अब हरियाली से जगमगा उठेंगे। वास्तव में इसे राजस्थान की लाइफ लाइन कह सकते हैं, जो बिल्कुल सटीक है।

परियोजना की तकनीकी बारीकियां भी कम आश्चर्यजनक नहीं हैं। नवनेरा बैराज पर कालीसिंध भविष्य में राम जल सेतु राजस्थान को जल निर्यातक बना सकता है। पड़ोसी राज्यों के साथ जल साझेदारी बढ़ेगी। सौर ऊर्जा से संचालित पंप और स्मार्ट सेंसर से जल प्रबंधन क्रांतिकारी होगा। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण, और किसानों को समृद्धि मिलेगी। यह परियोजना साबित करेगी कि इच्छाशक्ति से असंभव कुछ नहीं। अटल जी का सपना आज राजस्थान सरकार के हाथों साकार हो रहा है।

राम जल सेतु का सामाजिक प्रभाव गहरा होगा। ग्रामीण महिलाओं को अब दूर-दराज के जलाशयों से पानी लाने की मजबूरी नहीं रहेगी। बच्चे स्कूल जाने का समय बचाएंगे, और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। सिंचाई से कृषि उत्पादन में 30-40 प्रतिशत वृद्धि संभव है। गेहूँ, सरसों, बाजरा जैसी फसलें अब वर्ष भर होंगी। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को सस्ता जल मिलेगा, जो औद्योगिक इकाइयों के लिए वरदान सिद्ध होगा। राजस्थान की जीएसडीपी में 5-7 प्रतिशत का इजाफा अनुमानित है। पर्यावरणीय दृष्टि से, यह जल संरक्षण को बढ़ावा देगा, भूजल रिचार्ज होगा, और रेगिस्तानीकरण रुकेगा। नमामि गंगे जैसे अभियानों से प्रेरित होकर यह योजना स्वच्छ जल सुनिश्चित करेगी।

हालांकि चुनौतियां भी हैं। वन्यजीव अभयारण्यों से होकर गुजरने वाली नहरों में वन्यजीव सुरक्षा एक मुद्दा है। स्थानीय किसानों की जमीन अधिग्रहण पर विवाद हो सकते हैं, जिन्हें निष्पक्ष मुआवजा से हल करना होगा। जलवायु परिवर्तन से वर्षा अनिश्चित हो रही है, इसलिए जल संचयन क्षमता बढ़ानी होगी। केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता और मौसमी बाधाओं पर काबू पाना आवश्यक है। फिर भी, सरकार की सख्खिता से ये बाधाएं पार होंगी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल पहुंचाने का लक्ष्य अब वास्तविक लगता है।

राजनीतिक दृष्टि से यह परियोजना राजस्थान सरकार की उपलब्धि है। विपक्ष ने भले ही पर सवाल उठाए हैं, लेकिन वर्तमान प्रगति सप्रबूत है। राजस्थान सरकार का नेतृत्व और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का समर्थन इसे राष्ट्रीय महत्व का बना रहा है। मैं इसे रामायण के राम सेतु से जोड़कर देखता हूँ, भक्ति, कर्म और एकता का प्रतीक। ठीक वैसे ही, यह सेतु राजस्थान को सूखे के रावण से मुक्त करेगा।

भविष्य में राम जल सेतु राजस्थान को जल निर्यातक बना सकता है। पड़ोसी राज्यों के साथ जल साझेदारी बढ़ेगी। सौर ऊर्जा से संचालित पंप और स्मार्ट सेंसर से जल प्रबंधन क्रांतिकारी होगा। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण, और किसानों को समृद्धि मिलेगी। यह परियोजना साबित करेगी कि इच्छाशक्ति से असंभव कुछ नहीं। अटल जी का सपना आज राजस्थान सरकार के हाथों साकार हो रहा है।

राम जल सेतु राजस्थान की धरती को हराभरा बनाने का वचन है। यह स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जहां जल नदी नहीं, जीवन का आधार बनेगा। राज्य सरकार, इंजीनियरों और जनता की एकजुटता से यह सफल होगा। आइए, हम सभी इस अभियान का हिस्सा बनें, क्योंकि जल है तो जीवन है।

-अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कारपोरेट सलाहकार

भेदभावपूर्ण और गलत नीतियों से दलहन के किसान 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' से वंचित



रामपाल जाट

चने की फसल आने के पूर्व ऑस्ट्रेलिया से 2,34,800 टन चना देश में पहुंचने के समाचार हैं। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति क्विंटल घोषित है। बाजार भाव 4,800 से लेकर 5,200 रुपये प्रति क्विंटल है। सरकार की खरीद प्रभावी नहीं रहती है, खरीद का प्रबंधन ढीला-ढाला रहता है। किसानों की आय के संरक्षण के नाम पर राज्यों के कुल उत्पादन में से 75 प्रतिशत उत्पादन को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि से बाहर धकेला हुआ है। किसानों की रक्षार्थ भारत सरकार ने छत्रक योजना के रूप में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान वर्ष 2018 से आरंभ किया हुआ है, इस योजना की उद्देशिका में तिलहनों के साथ दलहन उपजों को भी लाभकारी मूल्य दिलाने का उल्लेख है। इसी योजना की मार्गदर्शिका में कुल उत्पादन में से 25 प्रतिशत से अधिक की खरीद को पर्यावरण अनुकूल भी है। प्रतिबंध को हटाया तो नहीं गया बल्कि 25 प्रतिशत से अधिक खरीद को सूट देने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के साथ सहयोग से यह परियोजना और मजबूत हुई है, क्योंकि योजना में दोनों राज्यों का हिस्सा है। हाल की प्रगति में जल्द ही 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है, जो राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राम जल सेतु का सामाजिक प्रभाव गहरा होगा। ग्रामीण महिलाओं को अब दूर-दराज के जलाशयों से पानी लाने की मजबूरी नहीं रहेगी। बच्चे स्कूल जाने का समय बचाएंगे, और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। सिंचाई से कृषि उत्पादन में 30-40 प्रतिशत वृद्धि संभव है। गेहूँ, सरसों, बाजरा जैसी फसलें अब वर्ष भर होंगी। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को सस्ता जल मिलेगा, जो औद्योगिक इकाइयों के लिए वरदान सिद्ध होगा। राजस्थान की जीएसडीपी में 5-7 प्रतिशत का इजाफा अनुमानित है। पर्यावरणीय दृष्टि से, यह जल संरक्षण को बढ़ावा देगा, भूजल रिचार्ज होगा, और रेगिस्तानीकरण रुकेगा। नमामि गंगे जैसे अभियानों से प्रेरित होकर यह योजना स्वच्छ जल सुनिश्चित करेगी।



डॉ. सौम्या गुर्जर

भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कभी शून्य नहीं रही, लेकिन यह हमारे समय तक निर्णायक भी नहीं बन पाई। प्रतिनिधित्व था, पर प्रभाव सीमित रहा और यही वह अंतर था, जिसने नीति-निर्माण को अधूरा रखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी कमी को दूर करने का एक ठोस और

आवश्यक प्रयास है। महिला आरक्षण का प्रश्न नया नहीं है। 1996 से यह विषय देश की राजनीति में मौजूद रहा, लेकिन दशकों तक यह सहमति और प्राथमिकता के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाया। वर्ष 2023 में इसे संवैधानिक स्वरूप मिला, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे में एक संरचनात्मक सुधार है। महामंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अधिनियम को जिस प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया, वह यह स्पष्ट करता है कि महिला सशक्तिकरण अब नीति का केंद्र है, न कि केवल एक सामाजिक विमर्श। महिला-नेतृत्व वाले विकास की अवधारणा इसी सोच का विस्तार है। भारत में महिलाओं का

प्रतिनिधित्व लंबे समय तक सीमित रहा लोकसभा में लगभग 15 प्रतिशत और कई विधानसभाओं में इससे भी कम। यह असंतुलन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं था; इसने नीति-निर्माण को दिशा को भी प्रभावित किया। जब निर्णय-प्रक्रिया में विविधता सीमित होती है, तो नीतियां भी सीमित दृष्टिकोण के साथ बनती हैं। वैश्विक अनुभव भी यही दर्शाता है कि जहाँ निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, वहाँ शासन अधिक संतुलित और संवेदनशील होता है। कई यूरोपीय देशों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि उनकी कम जनसंख्या उनके विकास का मुख्य कारण है यह आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं।

वास्तविक अंतर इस बात से आता है कि निर्णय लेने वालों की सोच कितनी

प्रतिक्रियात्मक है। हमारे समाज में यह अनुभव रहा है कि घर की घुंटी महिला होती है। वह केवल जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती, बल्कि संतुलन और दूरदर्शिता के साथ निर्णयों को दिशा देती है। परिवार के स्तर पर जो नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, वही जब शासन में स्थान पाता है, तो नीतियां अधिक संवेदनशील और समाज के वास्तविक संरोकारों से जुड़ी होती हैं। इस अधिनियम का महत्व केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव निर्णय-निर्माण की प्रकृति में बदलाव के रूप में दिखाई देगा। जब महिलाएं नीति-निर्माण का हिस्सा बनेंगी, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और बालिकाओं से जुड़े मुद्दे अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आएंगे। भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण ने पहले ही यह सिद्ध किया है कि अक्सर मिलने पर

प्रतिक्रियात्मक है। हमारे समाज में यह अनुभव रहा है कि घर की घुंटी महिला होती है। वह केवल जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती, बल्कि संतुलन और दूरदर्शिता के साथ निर्णयों को दिशा देती है। परिवार के स्तर पर जो नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, वही जब शासन में स्थान पाता है, तो नीतियां अधिक संवेदनशील और समाज के वास्तविक संरोकारों से जुड़ी होती हैं। इस अधिनियम का महत्व केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव निर्णय-निर्माण की प्रकृति में बदलाव के रूप में दिखाई देगा। जब महिलाएं नीति-निर्माण का हिस्सा बनेंगी, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और बालिकाओं से जुड़े मुद्दे अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आएंगे। भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण ने पहले ही यह सिद्ध किया है कि अक्सर मिलने पर

प्रतिक्रियात्मक है। हमारे समाज में यह अनुभव रहा है कि घर की घुंटी महिला होती है। वह केवल जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती, बल्कि संतुलन और दूरदर्शिता के साथ निर्णयों को दिशा देती है। परिवार के स्तर पर जो नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, वही जब शासन में स्थान पाता है, तो नीतियां अधिक संवेदनशील और समाज के वास्तविक संरोकारों से जुड़ी होती हैं। इस अधिनियम का महत्व केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव निर्णय-निर्माण की प्रकृति में बदलाव के रूप में दिखाई देगा। जब महिलाएं नीति-निर्माण का हिस्सा बनेंगी, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और बालिकाओं से जुड़े मुद्दे अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आएंगे। भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण ने पहले ही यह सिद्ध किया है कि अक्सर मिलने पर

उपकार, 4 मई 2024 से 31 मार्च 2025 तक शून्य कर दिया गया, 1 अप्रैल 2025 से 10 प्रतिशत है। पौली मटर के आयात के लिए 4 मई 2024 से 31 मार्च 2026 तक आयात शुल्क शून्य कर दिया गया। वर्ष 2015-16 में चने के आयात की मात्रा 10.3 लाख टन थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 16.1 लाख टन हो गई। इससे आयात पर खर्च की गई राशि 4,454 करोड़ से बढ़कर 10,307 करोड़ रुपए हो गई। भारत सरकार द्वारा चने के आयात पर आरोपित 60 प्रतिशत शुल्क को घटकर शून्य कर लाने का भी दुष्परिणाम किसानों को भुगतान पड़ रहा है।

देश में चने का क्षेत्रफल 2020-21 में 107 लाख हेक्टर से घटकर 2024-25 में 96 लाख हेक्टर रह गया। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि में बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के लगभग बराबर रहे। वर्ष 2022-23, 2023-24 2024-25 की 3 वर्षों की अवधि में देश के कुल उत्पादन में से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की भागीदारी दो तिहाई से अधिक है, जो क्रमशः 26.2 प्रतिशत, 24.4 प्रतिशत, 16.5 प्रतिशत है। गुजरात की भागीदारी 11.1 प्रतिशत को सम्मिलित करने पर इन चारों राज्यों की भागीदारी ही 78.2 प्रतिशत है। संयोग से देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं, जो चना उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री राजस्थान में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से हैं, जो चना उत्पादन में राजस्थान में अग्रिम पंक्ति में है, इसी क्षेत्र की विधानसभा दूर से निर्वाचित विधायक उपमुख्यमंत्री हैं। मूंग उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, इसी क्षेत्र की विधानसभा दूर से निर्वाचित विधायक उपमुख्यमंत्री हैं। मूंग उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, इसी क्षेत्र की विधानसभा दूर से निर्वाचित विधायक उपमुख्यमंत्री हैं। मूंग उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, इसी क्षेत्र की विधानसभा दूर से निर्वाचित विधायक उपमुख्यमंत्री हैं। मूंग उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, इसी क्षेत्र की विधानसभा दूर से निर्वाचित विधायक उपमुख्यमंत्री हैं।

रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान
महापंचायत

अब निर्णय-निर्माण में बढ़ेगी भागीदारी : नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नया भारत



डॉ. सौम्या गुर्जर

भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कभी शून्य नहीं रही, लेकिन यह हमारे समय तक निर्णायक भी नहीं बन पाई। प्रतिनिधित्व था, पर प्रभाव सीमित रहा और यही वह अंतर था, जिसने नीति-निर्माण को अधूरा रखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी कमी को दूर करने का एक ठोस और

आवश्यक प्रयास है। महिला आरक्षण का प्रश्न नया नहीं है। 1996 से यह विषय देश की राजनीति में मौजूद रहा, लेकिन दशकों तक यह सहमति और प्राथमिकता के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाया। वर्ष 2023 में इसे संवैधानिक स्वरूप मिला, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे में एक संरचनात्मक सुधार है। महामंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अधिनियम को जिस प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया, वह यह स्पष्ट करता है कि महिला सशक्तिकरण अब नीति का केंद्र है, न कि केवल एक सामाजिक विमर्श। महिला-नेतृत्व वाले विकास की अवधारणा इसी सोच का विस्तार है। भारत में महिलाओं का

प्रतिनिधित्व लंबे समय तक सीमित रहा लोकसभा में लगभग 15 प्रतिशत और कई विधानसभाओं में इससे भी कम। यह असंतुलन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं था; इसने नीति-निर्माण को दिशा को भी प्रभावित किया। जब निर्णय-प्रक्रिया में विविधता सीमित होती है, तो नीतियां भी सीमित दृष्टिकोण के साथ बनती हैं। वैश्विक अनुभव भी यही दर्शाता है कि जहाँ निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, वहाँ शासन अधिक संतुलित और संवेदनशील होता है। कई यूरोपीय देशों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि उनकी कम जनसंख्या उनके विकास का मुख्य कारण है यह आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं।

वास्तविक अंतर इस बात से आता है कि निर्णय लेने वालों की सोच कितनी

प्रतिक्रियात्मक है। हमारे समाज में यह अनुभव रहा है कि घर की घुंटी महिला होती है। वह केवल जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती, बल्कि संतुलन और दूरदर्शिता के साथ निर्णयों को दिशा देती है। परिवार के स्तर पर जो नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, वही जब शासन में स्थान पाता है, तो नीतियां अधिक संवेदनशील और समाज के वास्तविक संरोकारों से जुड़ी होती हैं। इस अधिनियम का महत्व केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव निर्णय-निर्माण की प्रकृति में बदलाव के रूप में दिखाई देगा। जब महिलाएं नीति-निर्माण का हिस्सा बनेंगी, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और बालिकाओं से जुड़े मुद्दे अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आएंगे। भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण ने पहले ही यह सिद्ध किया है कि अक्सर मिलने पर

प्रतिक्रियात्मक है। हमारे समाज में यह अनुभव रहा है कि घर की घुंटी महिला होती है। वह केवल जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती, बल्कि संतुलन और दूरदर्शिता के साथ निर्णयों को दिशा देती है। परिवार के स्तर पर जो नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, वही जब शासन में स्थान पाता है, तो नीतियां अधिक संवेदनशील और समाज के वास्तविक संरोकारों से जुड़ी होती हैं। इस अधिनियम का महत्व केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव निर्णय-निर्माण की प्रकृति में बदलाव के रूप में दिखाई देगा। जब महिलाएं नीति-निर्माण का हिस्सा बनेंगी, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और बालिकाओं से जुड़े मुद्दे अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आएंगे। भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण ने पहले ही यह सिद्ध किया है कि अक्सर मिलने पर

नेतृत्व उभरता है और शासन अधिक उत्तरदायी बनता है। यही अनुभव अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने जा रहा है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी केवल उपस्थिति नहीं, बल्कि प्रभाव के रूप में दिखाई देगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वास्तविक महत्व आने वाले वर्षों में सातों आयात, जब यह भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया को अधिक संतुलित और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाएगा। यह केवल सीटों का पुनर्वितरण नहीं, बल्कि नेतृत्व के पुनर्संतुलन की शुरुआत है। जब निर्णय-निर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित होगी, तब शासन अधिक संतुलित, संवेदनशील और भविष्य उन्मुख बनेगा और यही किसी भी विकसित राष्ट्र की वास्तविक पहचान है।

-डॉ. सौम्या गुर्जर,
जयपुर नगर निगम (ग्रेटर)

सीटों का परिसीमन और महिला आरक्षण: संवैधानिक कानूनी आधार, फिर हंगामा क्यों?



डा. योगेश शर्मा

16 से 18 अप्रैल 2026 तक भारतीय संसद के विस्तारित बजट सत्र की तीन दिवसीय विशेष बैठक का आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस बैठक के पहले में तीन अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं-संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026, तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026। इन प्रस्तावों के केंद्र में तीन परम्प्रेत जुड़े हुए मुद्दे हैं-जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण। यह भारतीय लोकतंत्र के ढांचे, उसकी प्रतिनिधिक क्षमता और उसके भविष्य के स्वरूप पर हो रहे वाला एक गहरा राष्ट्रीय विमर्श है। इन विधेयकों का संबंध न केवल भारत के संसदीय ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तन से है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, संघीय संतुलन और सामाजिक समावेशन जैसे मूलभूत प्रश्नों को भी छूते हैं। इससे पहले, वर्ष 2023 में पारित संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक, जिसे बाद में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में मान्यता मिली और जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में प्रस्तुत किया गया, ने लोकसभा और राज्य

विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया। अब वर्तमान प्रस्तावित संशोधन और परिसीमन प्रक्रिया इसी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अगला ताकिक कदम माने जा रहे हैं। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को 'जनता के प्रतिनिधि सदन' रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसे में सीटों का परिसीमन, लोकसभा और विधानसभाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि, और महिला आरक्षण जैसे विषय-लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विस्तार और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक संवैधानिक कदम हैं। फिर भी प्रश्न यह उठता है कि इन मुद्दों पर संवाद और बहस स्वाभाविक होने के बावजूद, इन्हें लेकर हंगामे का वातावरण क्यों बनाया जा रहा है?

यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारतीय संसद को वैधानिक और नैतिक जड़ें हमारी संविधान सभा में ही निहित हैं, जिसे सभा ने न केवल संविधान का निर्माण किया बल्कि स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में विधायी संस्था के रूप में भी कार्य किया। 1952 में प्रथम निर्वाचित लोकसभा के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या 489 थी। संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना निर्धारित की गई, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं की सीटों का पुनर्समायोजन किया जाना आवश्यक है। 1961 तथा 1971 की जनगणना के बाद भी परिसीमन हुआ। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह था कि पूरे देश में लगभग प्रत्येक संसदीय सीट समान आबादी का प्रतिनिधित्व करे, ताकि लोकतांत्रिक समानता बनी रहे। इनके आधार पर लोकसभा की सीटें 489 से बढ़कर 543 तक पहुंचीं, जबकि राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में भी वृद्धि हुई-जैसे राजस्थान विधानसभा की सीटें 160 से बढ़कर 200 तक हो गईं।

हालांकि, 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, देश की तत्कालीन परिस्थितियों और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि वर्ष 2000 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। बाद में, 2001 में 84वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर कर दिया गया। परन्तु इस नीति से जहाँ एक ओर जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन मिला, वहीं दूसरी ओर संसदीय लोकतंत्र के एक मूलभूत सिद्धांत-प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। विशेष रूप से, मतदाता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क में कमी आई।

सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर करने से प्रस्तुत प्रतिनिधित्व का संकट वर्तमान प्रस्तावों की पुष्टीपूर्ण तैयार करता है। संविधान के अनुसार, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें

अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। प्रस्तावित विधेयक में इस सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें अधिकतम 815 सदस्य राज्यों से तथा अधिकतम 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। वर्तमान में प्रस्तुत 131 वें संविधान संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 में संशोधन करते हुए परिसीमन और महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। सरकार का तर्क है कि यह केवल सीट वृद्धि का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को वर्तमान जनसंख्या-व्यथार्थ के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, महिला आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक राजनीतिक और संरचनात्मक स्थान भी इसी विस्तार के माध्यम से तैयार किया जा सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया संवैधानिक और विधिपरक है, और संसद में व्यापक बहस एवं मतदान के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

इस व्यापक विमर्श का महत्वपूर्ण आयाम महिला आरक्षण है। 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। यदि प्रस्तावित 850 सीटों में लगभग 280 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, तो बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए राजनीतिक द्वार खुलेंगे। महिला आरक्षण केवल राजनीतिक प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह देखा महत्वपूर्ण होगा कि वे राजनीतिक दल, जो लंबे समय से महिला सशक्तिकरण को बत करते रहे हैं, क्या वे इस संवैधानिक प्रावधान को वास्तविक रूप में लागू करने की प्रतिबद्धता दिखाते हैं।

जहाँ तक राजनीतिक विरोध का प्रश्न है, कुछ विपक्षी दलों और विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों को आशंका है कि परिसीमन प्रक्रिया जनगणना से पृथक होकर राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ने अपेक्षाकृत बेहतर जनसंख्या नियंत्रण किया है। सम्भवतः इन राज्यों को यह आशंका है कि जनसंख्या को प्रतिनिधित्व का आधार मानने पर अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को सीटों में बड़ी वृद्धि मिल सकती है, जबकि इन दक्षिणी राज्यों की राष्ट्रीय राजनीतिक हिस्सेदारी घट सकती है। सरकार का तर्क है कि सीटों की संख्या में अनुपातिक वृद्धि सभी राज्यों के लिए प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न हो।

हालांकि, यह भी तथ्य है कि 2026 में जनगणना प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो चुकी है-पहले आवास सूचीकरण और उसके बाद 2027 में जनगणना का चरण पूरा होने की संभावना है। साथ ही, लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से खुली होती है। यदि को दल इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देखता भी है, तो विधेयक के पास भी जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों और विचारों को प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण का यह त्रिकोण केवल संविधायी, विधायी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की पुनर्संरचना का वह क्षण है, जहाँ भारत अपने संवैधानिक आदर्शों को निष्पत्ति में लाने की संभावना है।

-डॉ. योगेश शर्मा,
संवैधानिक अध्येता और
अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ।

राशिफल शनिवार 18 अप्रैल, 2026

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शनिवार, विक्रम संवत् 2083, अश्विनी नक्षत्र प्रातः 9:45 तक, प्रीति योग रात्रि 11:56 तक, बर वरण दिन 2:11 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरु-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज चन्द्र दर्शन, दक्षिण श्रृंगोन्नति, देव दामोदर तिथि है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:40 से 9:15 तक, चर 12:26 से

2:02 तक, लाभ-अमृत 2:02 से 5:13 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:04, सूर्यास्त 6:48

मेष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य के लिए यात्रा संभव है।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में सार्थक सफलता मिल सकती है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

धनु
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी। अटक हुए कार्य बने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। परिवार में मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। आज अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ एवं नवीन कार्यों में व्यवधान हो सकता है। सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय

महिला आरक्षण विधेयक पराजित हुआ लोकसभा में, पर भाजपा जीती!

एनडीए को कुल 298 वोट मिले, आरक्षण विधेयक के पक्ष में, इंडिया अलायंस (कांग्रेस व विपक्ष) को 230 वोट, जबकि संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए दो तिहाई मत, यानि 364 वोट चाहिए थे

-रेणु मिश्र-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 17 अप्रैल। मोदी-शाह सरकार के लिए यह ऐतिहासिक पराजय जैसा है कि संविधान संशोधन महिला आरक्षण बिल गिर गया, क्योंकि सरकार तीन संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटा पाने में असफल रही।

एक दिन की भारी हलचल और शोर के बाद पहले वोटिंग राउंड का अंतिम परिणाम इस प्रकार रहा- एनडीए के पक्ष में 298, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि दो तिहाई बहुमत के हिसाब से सरकार को 489 सदस्यों को सदन में 360 मतों की जरूरत थी।

इस नतीजे को भाजपा की "जीत" इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि अब भाजपा को देश भर में दिवोरा पीटने के लिए मुद्दा मिल गया कि भाजपा तो महिलाओं को संसद में, विधानसभाओं में, एक तिहाई आरक्षण देने को तत्पर थी, पर, विपक्ष ने इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया।

भाजपा को उसके प्रयास के लिए स्वाभाविक ही है, देश भर में महिलाएं सराह रही हैं। जिसका लाभ भाजपा को चुनाव में, विशेषकर प.बंगाल के चुनाव में मिलेगा और यह शायद ममता बनर्जी को बंगाल में हराने में काफी मददगार साबित हो सकता है।

चूंकि अन्य दो बिल भी इसी से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें भी असफल माना गया और सरकार ने उनके लिए मतदान कराने का प्रयास नहीं किया। अमित शाह का भाषण इस बिन्दु पर केन्द्रित था कि कैसे महिला आरक्षण बिल विपक्ष द्वारा नाकाम किया गया और

देश की महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी। असलियत यह है कि महिला बिल को परिसीमन से जोड़ने के कारण विपक्ष ने फैसला किया कि वे देश को उत्तर और दक्षिण में विभाजित नहीं होने देंगे। विपक्ष ने पूरे दिन सरकार से कहा

कि परिसीमन बिल को हटाएँ, महिला आरक्षण बिल को अपने आप खड़ा होने दें, और वे इसे पास करेंगे, ताकि तुरंत लागू किया जा सके। विपक्ष ने कहा कि जनगणना के बिना परिसीमन स्वीकार्य नहीं है, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘चाणक्य होते तो, आपकी राजनैतिक चतुराई से चकित रह जाते’

-जाल खंबाता-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 17 अप्रैल। गृह मंत्री अमित शाह उस समय अन्य भाजपा नेताओं के साथ मुस्कराते दिखाई दिए, जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उन पर हँसी-मजाक के अंदाज़ में एक परोक्ष तारीफ की।

प्रियंका गांधी ने तीन बिलों में संशोधन और महिला आरक्षण विधेयक तथा परिसीमन आयोग के गठन पर बहस में हिस्सा लेते हुए अमित शाह की ओर इशारा करते हुए कहा, "वे हँस रहे हैं।"

प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक की समयावधि और ढाँचे के

■ प्रियंका गांधी ने अमित शाह की राजनैतिक चतुराई पर व्यंग्यात्मक अंदाज़ में टिप्पणी की और कहा, सारी तैयारी कर रखी है, इसीलिए वे हँस रहे हैं।

राजनीतिक इरादों पर सवाल उठाते हुए, मजाक में कहा, "गृह मंत्री जी हँस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य अगर होते, तो वो भी चकित रह जाते आपकी राजनैतिक चतुराई पर।" कांग्रेस नेता ने कहा, "उन्होंने (शाह) पूरी योजना बनाई और अब हँस रहे हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान ने अचानक "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़" को जहाजों के आवागमन के लिए खोलने की घोषणा की

इससे अमेरिका की स्थिति अटपटी, खिसयानी बिल्ली जो खंबा नोचे, जैसी हुई

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। अचानक ही मिडिल ईस्ट के सभी मोर्चों पर शांति का माहौल बनता दिख रहा है। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने की घोषणा की है, इजरायल और लेबनान युद्धविराम की बात कह रहे हैं, जिससे राजधानी बेरुत में जश्न का माहौल है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ईरान के जब्त किए गए 20 अरब डॉलर को अनफ्रीज करने पर विचार कर रहा है।

लेकिन स्पष्ट रूप से ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध में शांति की पहल अपने हाथ में ले ली है, और अमेरिका को पीछे छोड़कर एकतरफा घोषणा की है कि होर्मुज़ स्ट्रेट अब "सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला है।"

ईरानी कदम से महत्वपूर्ण जल मार्ग खोलने की खबर सुनते ही तेल की कीमतों में अचानक गिरावट आई। दुनिया भर के देश समुद्री क्षेत्र के व्यापार से जुड़े पक्ष ईरान की एकतरफा और अचानक घोषणा से चौंक गए हैं।

पेरिस में होर्मुज़ स्ट्रेट पर आयोजित एक बहुदलीय सुरक्षा सम्मेलन में, जिसमें सभी यूरोपीय नेताओं ने भाग

■ ट्रंप ने अपना महत्व जताते हुए, अपना ब्लॉकडै अभी कुछ समय और जारी रखने का ऐलान किया।

■ ट्रंप को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनके वहाँ खाड़ी युद्ध में मौजूद होते हुए, ईरान ने एक तरफा घोषणा करने की पहल, अमेरिका के हाथ से खींच ली।

■ यूरोपीय देश, फ्रांस के तत्वाधान में पेरिस में मिले और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोलने की प्रक्रिया पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं।

■ अपना ब्लॉकडै कुछ और समय तक जारी रखकर, अमेरिका, चीन से छेड़-छाड़ करता नजर आ रहा है। क्योंकि, चीन की "ऑयल" की जरूरत, मुख्य रूप से ईरान के ऑयल से पूरी होती है और अगर इस सप्लाई में अमेरिका का ब्लॉकडै बाधा उत्पन्न करता है, तो स्थिति विकट बन सकती है।

■ इसलिए संभावना यह बन रही है कि ईरान-अमेरिका शांति वार्ता शीघ्र ही प्रारंभ होगी।

लिया, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के प्रमुख ने कहा कि आईएमओ तकालत क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ होर्मुज़ स्ट्रेट के माध्यम से सुरक्षित मार्ग निर्धारित करने के लिए

संपर्क कर रहा है।

फ्रांस के नेतृत्व में यूरोपीय देशों के नेता पेरिस में होर्मुज़ स्ट्रेट के पुनः खुलने की निगरानी के लिए एक बहुदलीय बल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रूस से तेल खरीदने का तरीका बदलेगा भारत

भारतीय कंपनियों सीधे रूस से तेल खरीदने की बजाय मध्यस्थों से तेल खरीदने के विकल्प पर विचार कर रही हैं

-श्रीनंद झा-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 17 अप्रैल। अब, जब अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल के आयात पर अपनी अल्पकालिक छूट को समाप्त कर दिया है, तो क्या भारत अमेरिकी संबंधों को नुकसान पहुँचाए बिना रूसी तेल का आयात जारी रख सकता है?

भारत ने अपने कच्चे तेल खरीद के विकल्प बढ़ाने का काम किया है तथा कई देशों से तेल खरीद रहा है। इस लिहाज से, भारत से अपेक्षा नहीं की जाती कि वह रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार करने का तरीका बदलने की संभावना है।

अमेरिकी छूट अवधि के दौरान, भारत ने रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाया था तथा मार्च 2026 में यह

■ अमेरिका ने रूस से तेल आयात पर जो एक महीने की छूट दी थी उसे समाप्त कर दिया है, ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या भारत रूस से तेल खरीद जारी रखेगा या अमेरिकन दबाव में आकर तेल निर्यात बंद कर देगा? भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि रूस से तेल आयात जारी रहेगा, पर अलग तरीके से।

■ असल में रूस से भारत को कम कीमत में तेल मिल रहा है, भारत कदापि रूस से तेल खरीद बंद नहीं करना चाहता। पर, कुछ क्षेत्रों में शिपिंग जोखिम, सप्लाई चैन में बाधा से मामला कुछ संवेदनशील है। मध्यस्थों के जरिए तेल खरीद एक जटिल प्रक्रिया है तथा इसमें निगरानी रहने की भी संभावना है।

लगभग दो मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुँच गया। इससे रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन

गया। ऐसी संभावना है कि आगामी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने पाकिस्तान जाने के संकेत दिए

-जाल खंबाता- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वाइट हाउस के संवाददाताओं से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर चल रही कूटनीति से जुड़ा कोई समझौता अंतिम रूप ले लेता है, तो वह पाकिस्तान जा सकते हैं। मैं पाकिस्तान जाऊँगा, हाँ... इस्लामाबाद, मैं "मैं

■ अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा, अगर ईरान के साथ डील इस्लामाबाद में साइन होती है तो वे भी वहाँ जा सकते हैं।

शायद जाऊँगा, उन्होंने कहा। अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है, तो मैं जा सकता हूँ... वे मुझे चाहते हैं।"

उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों का उल्लेख सकारात्मक शब्दों में किया। "पाकिस्तान शानदार रहा है, वे बहुत अच्छे रहे हैं।" उन्होंने कहा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'डोन्ट डू ईट', परिसीमन पर थरुर ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी

कांग्रेस सांसद शशि थरुर ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि जल्दबाजी में किया गया परिसीमन राजनैतिक नोटबंदी साबित होगा

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। इसे मत करो, यह संदेश शुक्रवार को शशि थरुर ने केन्द्र सरकार को दिया, जब परिसीमन पर बहस चल रही थी, एक ऐसा कदम जो संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को नष्ट सिरे से तय करेगा।

कांग्रेस सांसद ने 2016 की नोटबंदी को चेतावनी की कहानी के रूप में उद्धृत किया और भाजपा नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार से कहा कि सीमांकन प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

थरुर ने कहा, "सहकारी संघवाद का क्या होगा? आपने परिसीमन का प्रस्ताव उतनी ही जल्दी में रखा है, जितनी जल्दी आपने नोटबंदी की थी... दुर्भाग्य से, हम जानते हैं कि इससे क्या नुकसान हुआ। परिसीमन राजनीतिक नोटबंदी साबित होगा। इसे मत करो।"

■ थरुर ने कहा, आपने परिसीमन का प्रस्ताव वैसी ही जल्दबाजी में रखा है, जितनी जल्दबाजी में नोटबंदी की थी और उससे कितना भारी नुकसान हुआ था, हम सब जानते हैं।

■ थरुर ने कहा, महिला आरक्षण पर हम सभी सहमत हैं। सरकार कहती है, यह न्याय का उपहार है, पर इसे कांटेदार तारों में लपेट दिया गया है। सरकार ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा है, जो 2011 जनगणना पर आधारित है।

■ ऐसा हुआ तो राज्यों के बीच भारी असंतुलन पैदा होगा।

महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक गुरुवार को लोकसभा में चोट

विभाजन के बाद पेश किया गया। दो अन्य साधारण विधेयक, परिसीमन विधेयक और केन्द्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित संशोधित महिला आरक्षण

कानून को लागू करने के लिए केन्द्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, भी सदन में पेश किए गए।

उन्होंने कहा, "आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं, जहाँ महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में लगभग सर्वसम्मत राजनीतिक सहमति है। हर प्रमुख पार्टी

यह समझती है कि प्रतीकात्मकता का समय समाप्त हो गया है और सामूहिक साझेदारी का युग शुरू होना चाहिए, फिर भी मैं खुद हमारे सामने चल रही विधायी प्रक्रिया को लेकर गहराई से चिंतित हूँ। सांसद ने कहा, "प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकार "नारी शक्ति" लायी है, यह न्याय का उपहार है, लेकिन इसे कांटेदार तारों में लपेट दिया गया है, और महिला आरक्षण के लागू होने को संसद विस्तार से जोड़ा गया है, जो 2011 की जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन प्रक्रिया पर आधारित है।"

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण तैयार है और मौजूदा संसदीय ताकत के आधार पर तुरंत लागू किया जा सकता है, और किया जाना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया, "श्रीमान अध्यक्ष, हमें एक नैतिक अनिवार्यता को जनसांख्यिकीय जाल में क्यों उलझाना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खंडपीठ ने वेटनरी ऑफिसर भर्ती की परीक्षा तिथि बदलने से इंकार किया

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरपीएससी की ओर से 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली वेटनरी ऑफिसर भर्ती-2025 परीक्षा की तिथि में बदलाव से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही,

■ अदालत ने याचिकाकर्ता को एकलपीठ के समक्ष लंबित याचिका में आपत्तियाँ उठाने को कहा।

अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह पात्रता संबंधी अपनी आपत्तियाँ एकलपीठ के समक्ष लंबित याचिका में उठाए। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने ये आदेश नरेन्द्र कुमार व अन्य की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'15 अप्रैल को हमने आदेश दिया, यहाँ नया आवेदन करने की बजाय आपने असम कोर्ट में आवेदन क्यों नहीं किया'

पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की

■ यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत दस्तावेज (गलत आधार कार्ड) पेश करने के लिए भी फटकारा। खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जल्दबाजी में दस्तावेज संलग्न किए गए थे इसलिए गलती हो गई, इस छोटी सी त्रुटि के कारण जमानत नहीं रोकी जा सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप फर्जी दस्तावेज पेश नहीं कर सकते। सिंघवी ने कहा, यह जल्दबाजी में हुई गलती थी, जिसे ठीक कर लिया गया था।

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सारा मामला असम का है तो खेड़ा असम की अदालत क्यों नहीं गए, उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख क्यों किया।

■ खेड़ा की ओर से उनके वकील ने अग्रिम जमानत मंगलवार तक बढ़ाने का आग्रह किया, जिसका असम सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया और कहा, असम की अदालत शुक्रवार को भी खुली है, खेड़ा को कोई भी रोक नहीं रहा है, वहाँ जाने से

अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के उस कथन का हवाला दिया कि उनके मुंबिकल ने उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन के साथ "जाली और फैंब्रिकेटेड" आधार कार्ड प्रस्तुत किया था। सिंघवी ने कहा कि, दस्तावेज जल्दबाजी में दाखिल किया गया था।

उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान इसे सही दस्तावेज से बदल दिया गया। सिंघवी ने कहा कि अदालत को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी गई।

सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की किसी टिप्पणी से जमानत याचिका को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ हाई कोर्ट ने सुंदरी देवी की याचिका पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेश दिए।

नियुक्ति दे। अदालत ने चेतावनी है कि नियुक्ति देने में एक दिन की भी देरी की गई तो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यदि मामले में विलंब हुआ तो अदालत स्वप्रेरणा से जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ करेगी। जस्टिस रवि चिरानिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चिकित्सा संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कार्नर

प्रदेश में लू-तापघात की आशंका को देखते हुए सरकार का निर्णय

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। प्रदेश में आगामी दिनों में लू-तापघात की आशंका को देखते हुए चिकित्सा संस्थानों में हीटवेव वचाव एवं उपचार के लिए समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इमरजेंसी सुविधाओं के लिए चिकित्सा संस्थानों में हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कोर्नर स्थापित करने के साथ ही दवा एवं जांच सहित सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।



चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को हीटवेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों की तैयारियों पर चर्चा की।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में हीटवेव प्रबंधन, मौसमी बीमारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्साधिकारी हीटवेव को लेकर प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ काम करें। रोगी और उनके परिवारों के लिए छाया, शीतल पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

राठौड़ ने कहा कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित चिकित्सालय प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में पंखे, कुकर, एसी, वाटर कूलर, जांच, दवा-ओआरएस एवं उपचार के प्रबंधन में कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने आवश्यकता होने पर दवाओं की स्थानीय स्तर पर खरीद करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी निरंतर फील्ड में जाकर चिकित्सा संस्थानों

का निरीक्षण करें। उन्होंने रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू कर रोगियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

राठौड़ ने गर्मी के मौसम को देखते हुए शुद्ध खाद्य पदार्थों एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि को नियंत्रण को भीडभाड वाले स्थानों, छात्रावासों सहित अन्य स्थानों पर खाद्य पदार्थों एवं पानी की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत एमएनए एवं सीएओ के कार्यों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी चिकित्सा संस्थानों में

- प्रमुख शासन सचिव ने दिए हीटवेव से बचाव एवं उपचार के समुचित प्रबंध करने के निर्देश
- अधिकारी रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करें : गायत्री राठौड़
- खाद्य पदार्थों व पानी की जांच तथा 2 दिनों में सभी एम्बुलेंस का सत्यापन कराने के निर्देश

अधिकारी के निर्देशन में सभी 108 एम्बुलेंस में साफ-सफाई, उपकरणों एवं दवाओं की उपलब्धता और क्रियाशीलता के संबंध में आगामी दो दिवस में सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

राठौड़ ने टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय अभियान, गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भवन निर्माण एवं भूमि आवंटन, ओडीओ के एम में सूचनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में प्रभावी रूप से कार्य कर सघन स्क्रीनिंग कर निर्धारित लक्ष्य अर्जित किए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वास्थ्य कैम्प की सूचना पूर्व में ही आमजन को दी जाए ताकि आमजन इन शिविरों का पूर्ण लाभ ले सकें। उन्होंने एचपीवी अभियान को भी गति देने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रमुख शासन सचिव ने प्रदेश में आपातकालीन रेफरल व्यवस्था के लिए 108 अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का पूर्ण लाभ ले सकें। उन्होंने एचपीवी अभियान को भी गति देने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अब 20 हजार वर्गमीटर से बड़े भूखण्ड भी होंगे उप-विभाजित

रीको प्रशासन ने लागू किए उप-विभाजन के नए नियम लागू

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको ने बड़े औद्योगिक भूखण्डों के उप-विभाजन को सफल मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय के तहत अब रीको के आवंटी अपने बड़े भूखण्ड छोटे हिस्सों में विभाजित कर विक्रय कर सकेंगे।

- इस निर्णय से बड़े भूखण्डों का बेहतर उपयोग होगा
- निवेशकों को उद्योग लगाने के अधिक अवसर मिलेंगे

न्यूनतम 18 मीटर तथा इससे बड़े भूखण्ड के लिए 24 मीटर का गैर औद्योगिक सड़क का प्रावधान रखा गया है।

वित्तीय प्रावधानों के तहत उप-विभाजन शुल्क संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर का 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ट्रांसफर चार्ज एवं एक स्वीकृत गतिविधि से अन्य स्वीकृत गतिविधि के परिवर्तन हेतु स्वीकृत शुल्क भी नियमानुसार देय होंगे। उप-विभाजित भूखण्ड की लीज अवधि मूल लीज अवधि से अधिक नहीं होगी और नए खरीदार को पंजीकृत दस्तावेज की तिथि से दो वर्षों के भीतर भूखण्ड का उपयोग करना अनिवार्य होगा। गौरवलेख है कि उद्यमियों द्वारा लंबे समय से बड़े भूखण्डों के उप-विभाजन की मांग की जा रही थी। ऐसे में यह निर्णय न केवल भूमि के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति देगा तथा नए निवेश एवं रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा।

रीको प्रशासन ने रीको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 के नियम 17 (ई) को पुनः लागू करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों का उप-विभाजन किया जा सकेगा। उप-विभाजन के बाद प्रत्येक उप-विभाजित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर रहेगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार, भूखण्ड का उप-विभाजन भूमि आवंटन के 7 वर्ष बाद ही किया जा सकेगा और संबंधित भूखण्ड विवाद रहित होना चाहिए। उप-विभाजन की प्रक्रिया के तहत आवेदक को प्रस्तावित लेआउट

प्लान रीको में जमा कराना होगा, जिसे लैंड प्लान कमेटी से अनुमोदित कराया जाएगा। यदि भूखण्ड पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण है, तो उसकी एनओसी भी आवश्यक होगी। रीको ने स्पष्ट किया है कि उप-विभाजन के बाद विकसित होने वाले क्षेत्र में सड़क, ड्रेनेज, बिजली, स्ट्रीट लाइट, वर्षा जल संचयन और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं मूल आवंटी को अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होंगी। इन सुविधाओं को तीन वर्षों के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। नियमों के अनुसार, 1500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड के लिए

चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक गूंजा नारी शक्ति का जयघोष



जयपुर में शुक्रवार को 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' का आयोजन किया गया।

जयपुर। महिला सशक्तिकरण और 'विकसित भारत' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जयपुर में 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' का आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में 'माय भारत' द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सुबह 7:30 बजे चांदपोल से शुरू हुई यह रन बड़ी चौपड़ तक आयोजित की गई। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में छात्राओं, उद्यमियों, पत्रकारों, खिलाड़ियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे मार्ग पर जोश और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की थीम 'नारी शक्ति वंदन' रखी गई। रन को राज्य मंत्री मंजू बाघमार और पूर्व विधायक अलका गुर्जर ने पलैंग-ऑफ किया। इस मौके पर पूर्व महापौर कुसुम यादव सहित कई प्रमुख महिलाएं उपस्थित रही। विशेष आकर्षण के रूप में कॉमनवेलथ गेम्स 2022 की संस्य फुटबल विजेता पूजा और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 की स्वर्ण पदक विजेता कचनार चौधरी ने भी भाग लेकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।

17 देशों के 43 प्रतिभागी रूबरू होंगे राजस्थान विधानसभा से : देवनानी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि शनिवार को विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिभागी राजस्थान विधानसभा का अवलोकन करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय परिषद कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, घाना, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, जांबिया सहित 17 देशों के 43 प्रतिभागी भाग लेंगे। स्पीकर देवनानी ने बताया कि

लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेंट्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसिस द्वारा इन्टरनेशनल लेजिस्लेटिव डीप्लॉमिंग विषय पर विधायी मसौदा तैयार करने के लिए 37 वें अंतर्राष्ट्रीय परिषद कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान विधान सभा में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी

एवं आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत संचालित हो रहा है। देवनानी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी प्रतिभागियों के लाभ के लिए विधायी मसौदा तैयार करने के वैचारिक विचार, कोशल और तकनीकी को बढ़ाना है। स्पीकर देवनानी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 18 अप्रैल को विदेशी प्रतिनिधियों का दल राजस्थान

विधानसभा के सदन, भवन और राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। इससे राज्य विधानमण्डल कि पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय परंपराओं की जानकारी दी जाएगी। देवनानी ने बताया कि प्रतिभागियों की पीठासीन

अधिकारियों और विधानसभा सचिव के साथ संवाद, प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों एवं गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात तथा राज्य के प्रमुख विधि संस्थानों का भ्रमण भी कराया जाएगा। स्पीकर देवनानी ने बताया कि विदेशी प्रतिभागियों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से परिचित कराने हेतु स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा।

पत्नी से परेशान युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की

मरने से पहले युवक ने अपनी बहन को सुसाइड नोट भेजा था

जयपुर (कांस)। मुहाना इलाके में गत 21 फरवरी की रात एक युवक ने अपनी पत्नी से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने मृतक की बहन के मोबाइल पर आए मैसेज के आधार पर हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पीड़ित पिता सांगनेर के वैष्णव नगर निवासी रामनिवास बाधम ने अपनी बहन के खिलाफ आमहत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

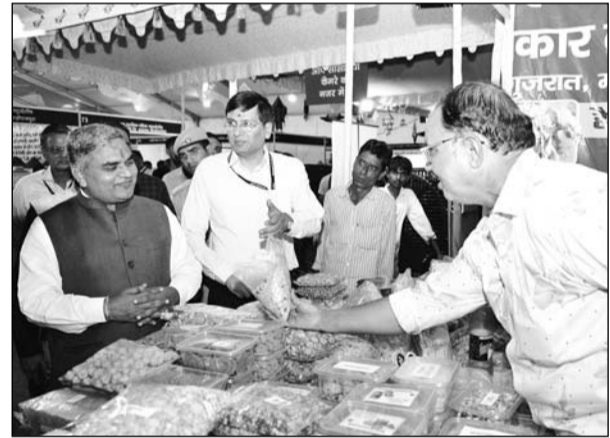
मृतक के पिता का आरोप है कि मई-2011 में संदीप (38) की शादी उत्तर प्रदेश निवासी लड़की से हुई थी। संदीप ने 21 फरवरी को रात करीब 2:17 बजे अपनी बहन पायल को वॉट्सऐप पर मैसेज भेजा था, जिसमें अपनी पत्नी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिकायत में बताया कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी की ओर से झगड़ा करना शुरू कर

रिलायंस ने की "डिजिटल डिस्काउंट डेज़" की घोषणा

जयपुर (कांस)। रिलायंस डिजिटल ने अक्षय तृतीया से पहले "डिजिटल डिस्काउंट डेज़ कैम्पेन" की घोषणा की है। इसमें ग्राहकों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान ही नहीं, बल्कि फायदेमंद भी होगा। इस कैम्पेन के अंतर्गत, ग्राहक लीडिंग बैंक के काइर्स पर 26 हजार तक इंस्टैंट डिस्काउंट का फायदा तथा पेपर फाइनेंस पर 30000 तक कैशबैक का विकल्प मिल सकेगा। इसके अलावा, रिलायंस डिजिटल सैंकड प्रोडक्ट पर प्लैट 50 प्रतिशत की छूट देगा, जिससे ऑडियो डिवाइस, विनरेबल्स, मोबाइल और लैपटॉप एक्ससेरीज, चुनिंदा होम एंटरटेनमेंट और छोटे अप्लायसेज जैसी इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें जैसे वायरलेस माउस, लैपटॉप एक्ससेरीज, पावर बैंक और सैंडविच मेकर जैसे छोटे देवैदर गुला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी में बढते यातायात दबाव को कम करने के लिए जून-7 में सिरसी रोड (सी.जो. बाईपास से सिरसी मोड तक) के चौड़ीकरण एवं विकास कार्य हेतु 48.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा सीकर रोड पर चौमू पुलिसिया रोड नंबर 14 तक एट-ग्रेड यू-टर्न निर्माण के लिए 9.54 करोड़ तथा

सहकारिता मंत्री ने किया मसाला मेले का शुभारम्भ

जयपुर (कांस)। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दक ने कहा कि सहकारिता विभाग एवं कॉन्फेड द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को एक सशक्त मंच मिलता है तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है। दक ने शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र में शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा को मौजूदगी



सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने जवाहर कला केन्द्र में मसाला मेले का उद्घाटन करने के बाद स्टॉल्स का अवलोकन किया।

की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉन्फेड) द्वारा वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के मसाले एवं अन्य उत्पाद उपलब्ध होते हैं, जिससे यह आयोजन जयपुरवासियों के बीच लोकप्रिय बन गया है। इस वर्ष यह

मेला 17 से 26 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में इस बार लगभग 150 स्टॉल्स लगाई गई हैं। मेले में राजस्थान के साथ-साथ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि विभिन्न राज्यों की सहकारी संस्थाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रही हैं। साबुत एवं पिसे मसालों के अलावा विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पाद भी यहां उपलब्ध हैं।

जनगणना-2027 का पहला चरण 16 मई से

जयपुर (कांस)। जनगणना 2027 के तहत राजस्थान में प्रथम चरण का कार्य 16 मई से शुरू होकर 14 जून तक किया जाएगा। इस चरण में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि इस बार जनगणना को पूर्णतः डिजिटल और सहभागी बनाने की दिशा में 'स्व-गणना' की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत नागरिक 1 मई से 15 मई के बीच ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। हालांकि, इसके बाद भी प्रणाली द्वारा फील्ड स्तर पर सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्होंने साइबर सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि नागरिक केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी के साथ साझा न करें। राज्य में इस कार्य के लिए करीब 1 लाख 60 हजार प्रणाली और पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे, जो घर-घर जाकर डेटा संग्रहण करेंगे। मकान सूचीकरण के दौरान भवनों, परिवारों, उपलब्ध सुविधाओं, परिसंपत्तियों तथा उपभोग से जुड़े कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रथम चरण का उद्देश्य

■ आरोपी की मदद करने वाले दो युवकों को भी पुलिस ने दबोचा

आगामी जनसंख्या गणना के लिए एक सटीक और विश्वसनीय मास्टर फ्रेम तैयार करना है, ताकि दूसरे चरण में कोई भी व्यक्ति या परिवार गणना से वंचित न रह जाए। जनगणना कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्यभर में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स और प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए पोर्टल, वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, जिनसे निगरानी और डेटा संग्रहण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। निदेशक मल्लिक ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करते हुए सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं तथा प्रणाली के पहचान पत्र और कोड की जांच के बाद ही जानकारी साझा करें।

पाइप लाइन गैस कनेक्शन बढ़ाने के निर्देश

जयपुर। जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) अर्णव अरोरा ने राज्य की सीजीडी (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइड नेचुरल गैस) कनेक्शन से जोड़ें। सचिवालय में आयोजित वृत्तअल बैठक में उन्होंने कहा कि सीजीडी संस्थाएं जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को पाइपलाइन से घरेलू गैस सुविधा से जोड़ें और चरणबद्ध तरीके से कॉलोनिनों को एलपीजी प्री जोन घोषित करने की कार्ययोजना तैयार करें। अरोरा ने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर नियमित मॉनिटरिंग करें और प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। जैहं पीएनजी का आधारभूत ढांचा तैयार है, वहां कॉलोनी स्तर पर शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक कनेक्शन जारी किए जाएं।

पीडब्ल्यूसी बैठक में 286 करोड़ रु. के विकास कार्यों को मंजूरी

राजधानी में यातायात व सीवरेज सुधार तथा सौंदर्यीकरण पर जोर दे रहा जे.डी.ए. प्रशासन

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की पीडब्ल्यूसी (पब्लिक वर्क्स कमेटी) की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को जेडीसी सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से सीवरेज, यातायात सुधार और सड़क विकास सहित विभिन्न कार्यों के लिए करीब 286 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं। बैठक में सचिव गौरव सैनी, निदेशक आयोजना मृगाल जोशी, निदेशक अभियांत्रिकी देवेन्द्र गुला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी में बढते यातायात दबाव को कम करने के लिए जून-7 में सिरसी रोड (सी.जो. बाईपास से सिरसी मोड तक) के चौड़ीकरण एवं विकास कार्य हेतु 48.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा सीकर रोड पर चौमू पुलिसिया रोड नंबर 14 तक एट-ग्रेड यू-टर्न निर्माण के लिए 9.54 करोड़ तथा



जेडीए कमिश्नर सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को पब्लिक वर्क्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई।

सहकार मार्ग स्थित इमली फाटक और ज्योति नगर टी-जंक्शन सुधार के लिए 5.96 करोड़ रुपए की कार्यों स्वीकृति जारी की गई। शहर में सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जून-5 और 6 से एस्टपीपी नेवटा तक

लेटरल सीवर लाइन बिछाने के लिए 95.16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं भांकोरडी एरिया असफाल क्षेत्रों से एस्टपीपी नेवटा तक सीवर लाइन के लिए 42 करोड़ और ग्राम गजधरपुरा स्थित 30 एमएलडी एस्टपीपी के अपग्रेडेशन

हेतु 17.18 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति दी गई। शहरी सौंदर्यीकरण के तहत विद्याधर नगर के सेंट्रल स्पाइन कॉरिडोर पर सेंट्रल फूड स्ट्रीट के पुनर्विकास एवं रखरखाव के लिए 3.38

करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा सेक्टर-1 विद्याधर नगर में इफॉर्मेशन बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट सेंटर निर्माण हेतु 10.50 करोड़ तथा स्वर्ण जयंती गार्डन की चारदीवारी के लिए 3.02 करोड़ रुपए मंजूरी किए गए। जून-11 के अचरावाला, जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला और अभयपुरा में लैंड पुलिंग स्कीम के तहत सड़क एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 40.07 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मालवीय नगर के लिए 6.85 करोड़ तथा जाहोता प्लांट/ओवर से जाहोता गांव तक सड़क निर्माण के लिए 3.71 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बैठक में शहर के समग्र विकास, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर व्यापक चर्चा की गई।

एक किलो अफीम के साथ दो गिरफ्तार

जयपुर। राजधानी जयपुर के बगरू थाना क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से करीब 1 किलो अफीम बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ठाकुरिया टोल प्लाजा पर चल रही सघन नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार को रुकवाकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से करीबन 1 किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी विपुल जाट और राहुल सारण को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी चित्तौड़गढ़ से जयपुर अफीम की सप्लाई के लिए आ रहे थे। पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क बड़े स्तर पर नशे की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। यह कार्रवाई बगरू थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में की गई। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और तस्करी के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

जनमानस ने मन बनाया, प.बंगाल में भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने सिलीगुड़ी में कहा कि बंगाल की जनता तृष्णिकरण व भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं

सिलीगुड़ी/जयपुर, 17 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति से जनता त्रस्त है। ममता जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का विकास अवरूद्ध हो गया है, सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है तथा घुसपैटियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, भाजपा का संकल्प है, साफ नीयत, स्पष्ट नीति और तेज गति से विकास। पश्चिम बंगाल में जनमानस ने

■ **मुख्यमंत्री ने सिलीगुड़ी में मारवाड़ी समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के पक्ष में रोड शो में भाग लिया।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के समर्थन में आयोजित भव्य रोड शो में भाग लिया।

भाजपा के पक्ष में मन बना लिया है और यहां भाजपा की सरकार भारी बहुमत से जीतेगी। शर्मा शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित मारवाड़ी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी देश और दुनिया में राजस्थान की संस्कृति और परम्परा को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मारवाड़ी लोगों को अपने परोपकारी कार्यों के लिए देश-दुनिया में जाना जाता है। प्रवासी

राजस्थानी केवल आर्थिक गतिविधियाँ ही नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज ने कर्मभूमि में अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाएँ, गौशाला और देवालय बनवाकर सेवा भाव का परिचय दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में केन्द्र सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत 520 किमी लंबा गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड

एक्सप्रेस-वे बना रहा है, जिससे अब यूपी से बंगाल की दूरी घंटों में सिमट जाएगी। साथ ही, कोलकाता-सिलीगुड़ी के बीच 6-लेन हाईवे और बागडोगरा एयरपोर्ट का नया आधुनिक टर्मिनल यहां के व्यापार और पर्यटन की तस्वीर बदल देगा।

मुख्यमंत्री ने सिलीगुड़ी में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के समर्थन में आयोजित भव्य रोड शो में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित

जनसमूह ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर आमजन का अभिवादन स्वीकार किया। शर्मा का विभिन्न स्थानों पर लोगों में फूल-मालाओं से अभिनंदन किया। 'भारत माता की जय' 'जय श्री राम' और भाजपा के समर्थन में लगे नारों से पूरा वातावरण गुंज उठा। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे।

खंडपीठ ने वेटनरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में कहा गया कि आरपीएससी ने गत 17 जुलाई को वेटनरी ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें उन अर्थाधिकारियों को भी आवेदन करने की अनुमति दी गई, जो पाठ्यक्रम के अंतिम साल में थे या इंटरनिश कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग ने 19 अप्रैल, 2026 को भर्ती परीक्षा तय की है, लेकिन उस समय तक उनकी इंटरनिश पूरी नहीं हुई है। पशुपालन विभाग ने भी गत 9 नवंबर को परीक्षा तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी हस्तक्षेप किया

रूस से तेल खरीदने ...

गया, लेकिन आयोग ने तिथि नहीं बढ़ाई। इसके अलावा, पशुपालन विधि ने भी आयोग को पत्र लिखकर इंटरनिश में देरी के कई कारण बताए थे। ऐसे में परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। इसका विरोध करते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि अर्थाधिकारियों को प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं और सभी बीस परीक्षा केंद्रों पर सारी तैयारी कर ली गई है।

यदि परीक्षा टाली गई तो चयन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी। इसके अलावा हाईकोर्ट की एकलपीठ भी परीक्षा तिथि में बदलाव से इनकार कर चुकी है। मामले को सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने परीक्षा तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

रूस से तेल खरीदने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) महीनों में रूस भारत के लिए तेल का एक प्रमुख स्रोत बना रहेगा, लेकिन व्यापार करने का तरीका बदल सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय रिफाइनरी कंपनियां आने वाले महीनों में सीधे प्रतिबंधित रूसी फर्मों से डील करने से बचेंगी और इसके बजाय, व्यापार मध्यस्थों का उपयोग करना पसंद करेंगी। साथ ही, भारत शिपिंग और भुगतान के लिए कड़ी अंगुलान जांच का पालन करेगा।

अमेरिकी छूट का उद्देश्य खाड़ी संकट के बीच वैश्विक तेल आपूर्ति में अचानक व्यवधान को रोकना था। इस छूट ने सुनिश्चित किया कि कट-ऑफ तिथि से पहले समुद्र में भेजा गया कच्चा

तेल अभी भी खरीदारों तक पहुँच सके। इससे वैश्विक बाजार स्थिर रहने में मदद मिली। भारतीय रिफाइनरी कंपनियां रूसी आपूर्तिकर्ताओं की ओर अधिक आकर्षित हुईं, क्योंकि उन्होंने कम कीमत और बड़ी मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध कराया।

वैश्विक तेल बाजार भू-राजनीतिक तनाव, कुछ क्षेत्रों में शिपिंग जोखिम और स्प्लॉइ चैन में व्यवधान के कारण, कीमत के मामले में संवेदनशील बना हुआ है। इसलिए, भारत कम से कम कुछ समय रूसी तेल की खरीद जारी रख सकता है, हालांकि व्यापार का तरीका अधिक जटिल होने की ओर सतर्क निगरानी रहने की संभावना है।

हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिये

लखनऊ, 17 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश ने कांग्रेस सांसद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का आदेश जारी होने के बाद एक बार फिर यह मामला गरमा गया है। कोर्ट में दायर अर्जी में गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया गया है। दरअसल, राहुल गांधी के रायबरेली से सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता रखने का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सांसद भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता भी रखते हैं।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रारंभिक दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में शुरुवार को सुनवाई हुई।

ईरान से भारत ने 2361 लोगों को सुरक्षित निकाला

विदेश मंत्रालय ने बताया इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका व गुयाना का एक-एक नागरिक भी शामिल हैं

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत ने पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक, ईरान से अपने एवं मित्र देशों के 2361 नागरिकों को आमंत्रित किया और अजरबैजान के रास्ते से सुरक्षित निकाला है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, "संघर्ष के प्रकोप के बाद से हमने 2,361 नागरिकों को ईरान से सुरक्षित रूप से निकालने में मदद की है। इनमें से 2,060 आमंत्रित के माध्यम से और 301 अजरबैजान के माध्यम से आए हैं। इन 2,361 लोगों में 1,041 भारतीय छात्रों के साथ तीन विदेशी भी शामिल हैं। एक बांग्लादेश से, एक श्रीलंका से और एक गुयाना से है।" उन्होंने कहा कि ईरान में अभी भी

■ **विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान में अभी भी 6 से 7 हजार भारतीय मौजूद हैं।**

6000 से 7000 भारतीय मौजूद हैं। पश्चिम एशिया संकट पर एक अंतर-मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन ने भी कहा, "सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में निगरानी करना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्रालय में एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष परिचालन कर रहा है और हमारे मिशन के साथ समन्वय में काम कर रहा है। स्थानीय सरकार के दिशानिर्देशों, उड़ान और यात्रा की स्थिति, कासुलर

सेवाओं और हमारे समुदाय का समर्थन करने के लिए किए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों से संबंधित जानकारी के साथ अपडेटेड सलाह जारी की जा रही है।"

महाजन ने कहा कि इस क्षेत्र से भारत के लिए उन देशों से उड़ानें जारी हैं, जहां हवाई क्षेत्र खुला है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अब तक ईरान से आमंत्रित और अजरबैजान तक 2,358 भारतीय नागरिकों को भारत की ओर की यात्रा के लिए आवाजाही की सुविधा प्रदान की है। इजराइल का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से प्रतिबंधित उड़ान संचालन के साथ खुला है। हम जॉर्डन और मिस्र के माध्यम से इजरायल से भारतीय नागरिकों की यात्रा को भारत तक सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध की समीक्षा कर रहा है

साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता ने कहा कि समीक्षा में न्यायिक व आंतरिक कानूनी प्रक्रियायें शामिल हैं

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले में शुक्रवार को स्पष्ट किया कि इससे जुड़ी एक याचिका की समीक्षा की जा रही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में शेख हसीना के मुद्दे पर कहा कि इस संबंध में एक अनुरोध विचारधीन है, जो चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा है। भारत इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से संवाद जारी रखेगा और हर स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रचनात्मक जुड़ाव को भारत की इच्छा दोहराई है और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है।

दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को और गहरा करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से प्रस्तावों को विचार करने पर सहमत जताई है। वहीं,

■ **प्रवक्ता ने बताया कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर भारत ब्रिटेन से लगातार संपर्क में है।**

देश के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़े प्रश्न पर जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले में ब्रिटेन के साथ लगातार संपर्क में है। इस विषय में कानूनी प्रक्रिया जारी है और भारत सरकार इस पर करीबी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की स्पष्ट नीति है कि देश से भागे हुए आर्थिक अपराधियों को वापस लाकर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। सरकार इस दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और संबंधित देशों के साथ समन्वय के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत के तीन दिवसीय दौर पर आए थे। उन्होंने भारत सरकार से

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सौंपने की मांग की थी।

■ **ट्रंप ने ... (प्रथम पृष्ठ का शेष)**

ट्रंप के बयान ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका मध्य पूर्व में कई कूटनीतिक प्रयास आगे बढ़ा रहा है, जिसमें ईरान के साथ बातचीत और इजरायल-लेबनान सीमा पर तनाव रोकने की कोशिशें शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि हिज्जबुल्लाह के मामले में लेबनान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वे हिज्जबुल्लाह का ध्यान रखेंगे... वे अभी हिज्जबुल्लाह पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो वह मिडिल ईस्ट की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा... सही समय पर।" इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका का कूटनीतिक दायर दक्षिण एशिया का मध्य पूर्व तक बढ़ रहा है, और वह ईरान और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रगति चाहता है।

होर्मुज खुलने से तेल की कीमत 10 प्रतिशत घटी

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने की घोषणा के बाद शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस कदम से फारस की खाड़ी से तेल टैंकरों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, जिससे दुनिया भर में ग्राहकों तक कच्चे तेल की आपूर्ति

■ **बैंच मार्क माने जाने वाले अमेरिकी क्रूड की कीमत 81.28 डॉलर प्रति बैरल हो गई।**

सुचारू हो सकेगी। कच्चे तेल की आपूर्ति बहाल होने और भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद के बीच अमेरिकी शेयर बाजार एक और रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़े पाए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब स्थिति से बचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेरिका सबसे बड़ा और सीधा असर ऊर्जा बाजार पर दिखा है।

“डोन्ट डू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहिए? महिला आरक्षण तैयार है... इसे परिसीमन से जोड़ना भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं को हमारे देश के सबसे विवादास्पद और जटिल प्रशासनिक कवायद में बंधक बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को उनका आरक्षण देने का समर्थन करती है।

थरु ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया से उन राज्यों के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया है और जिन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सरकार से कहा, "कोई भी परिसीमन प्रक्रिया जटिलताओं से भरी होती है, जो हमारे संघवाद के मूल ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती है।

परिसीमन प्रक्रिया पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इसे जल्दीबाजी में नहीं किया जा सकता। महिला आरक्षण बिल आज पारित करें, हम उसका समर्थन करेंगे। जहाँ तक परिसीमन का प्रश्न है, इसे टाल दें। महिलाओं को उनका आरक्षण दें, कृपया देश के बड़े हित पर विचार करें।

कोलकाता में तृणमूल नेताओं पर ईडी व इनकम टैक्स की रेड

ईडी व इनकम टैक्स की टीमों ने शुक्रवार सुबह से ईडी अलग-अलग स्थानों पर रेड की

कोलकाता, 17 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच राज्य में केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाही लगातार जारी है। जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक रियल एस्टेट कंपनी और एक निर्माण संस्था के ठिकानों पर छापेमारी की, वहीं आयकर विभाग की तरफ से रासबिहारी के तृणमूल उम्मीदवार देबाशीष कुमार के घर सहित कई स्थानों पर दबिश दी गई। शुक्रवार सुबह सीओओ कॉम्प्लेक्स से ईडी की कई टीमों पहुंचीं। उनके साथ केन्द्रीय बल भी थे।

ईडी की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह से ही एक रियल एस्टेट कंपनी के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ईडी के अधिकारी साइट लेक और कोलकाता में चार जगहों पर पहुंचे हैं। उन्होंने न

■ **रासबिहारी के तृणमूल प्रत्याशी देबाशीष कुमार के घर इनकम टैक्स की रेड हुई वहीं एक रियल एस्टेट कंपनी पर ईडी ने छापेमारी की।**

केवल रियल एस्टेट कंपनी, बल्कि एक अन्य निर्माण कंपनी के कार्यालय पर भी छापेमारी की।

सूत्रों के मुताबिक, ये सर्च ऑपरेशन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले को लेकर है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इस कंप्यूटरकन कंपनी से जुड़े चर्च, प्लैटों और दफ्तरों में तलाशी अभियान

चलाया गया था। ईडी ने दावा किया कि यह ऑपरेशन चुनाव से पहले अवैध वित्तीय लेनदेन को रोकने और कुछ भूमि संबंधी मामलों में लेनदेन की जानकारी खोजने के लिए था।

दूसरी ओर, ईडी के अलावा एक अन्य केन्द्रीय एजेंसी आयकर विभाग भी कोलकाता में तलाशी अभियान चला रहा है। उन्होंने शुक्रवार सुबह रासबिहारी निर्वाचन क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार देबाशीष कुमार के घर सहित कई स्थानों पर दबिश दी।

आयकर विभाग की एक टीम शुक्रवार सुबह रासबिहारी के निवर्तमान विधायक देबाशीष के मनोहरपुर रोड स्थित घर पहुंची। न सिर्फ उनके घर, बल्कि मनोहरपुर रोड स्थित उनके चुनाव कार्यालय पर भी आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा था।

‘एक माह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की एकलपीठ ने यह आदेश सुंदरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ साल 2023 में तय कर चुकी है कि वह भी बेटी के समान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है, तो यह जानते हुए भी विभाग की ओर से जवाब में वही आर्पित उठाई गई है, जिसे पूर्व में खारिज किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पति की भी छह साल पूर्व मौत हो चुकी है। ऐसे में परिवार के सभी आश्रित याचिकाकर्ता पर ही निर्भर है। याचिका में अधिवक्ता आरसी गौतम ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के ससुर सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदस्थपति थे। इस दौरान 19 नवंबर, 2016 को उनकी मौत हो गई। याचिकाकर्ता के पति का पिता के जीवनकाल में ही एक्सिडेंट हो गया था और वह पूरी तरह से बेड पर आ गया था। ऐसे में याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभाग ने उस पर विचार नहीं किया। मामले पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को एक माह में नियुक्ति देते हुए, पालना रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।

ईरान में 48 दिन बाद गूगल सर्च सेवा बहाल

ईरान ने युद्ध शुरू होने पर इंटरनेट बंद कर दिया था उसमें अब आंशिक राहत देनी शुरू कर दी है

तेहरान, 17 अप्रैल। ईरान में करीब 48 दिनों तक चले इंटरनेट प्रतिबंधों के बाद आंशिक अब राहत मिली है। देश में अब गूगल सर्च सेवा बहाल कर दी गई है, जिससे आम नागरिक फिक्स्ड लाइन और मोबाइल इंटरनेट के जरिए संचर् इंजन का उपयोग कर पा रहे हैं। हालांकि, इंटरनेट कनेक्टिविटी अब भी पूरी तरह स्थिर नहीं हो सकी है और कई जगह पर उतार-चढ़ाव का स्वरूप बनी हुई है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जहाँ एक ओर गूगल सर्च की वापसी हुई है, वहीं जीमेल समेत, अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं अब भी बंद हैं। इससे स्पष्ट है कि देश में इंटरनेट सेवाएं अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई हैं और डिजिटल गतिविधियों पर आंशिक

■ **अभी भी जीमेल सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं बंद हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अस्थिर है।**

प्रतिबंध जारी है।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य संघर्ष के बाद ईरान सरकार ने देश में इंटरनेट पर सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। इस दौरान आम नागरिकों के लिए इंटरनेट एक्सेस लगभग बंद कर दिया गया था। केवल कुछ सीमित यूजर्स, जैसे सरकारी नेटवर्क से जुड़े लोग या वरुअल प्राइवेट नेटवर्क (वोपीएन) का इस्तेमाल करने वाले-ही इंटरनेट

का उपयोग कर पा रहे थे।

तेबे समय तक इंटरनेट बंद रहने का देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि इन पाबंदियों के चलते ईरान को करीब 1.8 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। ई-कॉमर्स, डिजिटल सेवाओं और छोटे व्यवसायों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। सरकार की ओर से इंटरनेट सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी सेवाएं पूरी तरह कब तक सामान्य हो पाएंगी। फिलहाल, आंशिक बहाली को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन पूर्ण डिजिटल सामान्य स्थिति बहाल होने में अभी समय लग सकता है।

‘15 अप्रैल को हमने आदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "अदालत को गुमराह किया गया। मैंने एक छोटा सा वृत्तपूर्ण दस्तावेज दाखिल किया, और कोर्ट का यह अवलोकन अग्रिम जमानत पर निर्णय लेने वाली किसी भी अदालत को बाध्य नहीं करेगा।

बैंच ने टिप्पणी की, "छोटी गलती? आप जाली और फ़ैब्रिकेटेड दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते। और हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि असम पुलिस ने अदालत को गुमराह कर आदेश लिया है।"

बैंच ने दोहराया कि जब किसी सक्षम अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया जाता है, तो इसे ट्रांजिट जमानत देने या उसे रोकने के आदेश से प्रभावित नहीं किया जा सकता।

असम पुलिस की ओर से पेश सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने खेड़ा की अग्रिम जमानत को बढ़ाने के प्रयास का विरोध किया। मेहता ने कहा कि खेड़ा

को असम में जिला अदालत जाने से कोई नहीं रोक रहा, जो शुक्रवार को खुली है।

असम पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, यह कहते हुए कि खेड़ा "जाली" दस्तावेजों के आधार पर उच्च न्यायालय गये। पुलिस ने कहा कि कथित अपराध, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां खेड़ा ने आरोप लगाए, असम में हुईं और मामला असम में दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने कहा कि खेड़ा के आधार कार्ड पर उनका दिल्ली का पता दर्ज था।

खेड़ा ने तर्क दिया कि उनकी पत्नी हैदराबाद की निवासी हैं और वहां विधानसभा चुनाव लड़ी थीं। "यह मूल रूप से मानहानि का मामला है, और सिर्फ इसलिए कि मैंने मुख्यमंत्री को नाराज किया, 100 पुलिसकर्मी दिल्ली भेज दिए गए।"

असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और पवन खेड़ा के बीच विवाद तब शुरू हुआ, जब खेड़ा ने प्रेस से हुई

बातचीत में सन्दर्भित टिप्पणी की।

उन्होंने दावा किया कि सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन सक्रिय विदेशी पासपोर्ट हैं और अमेरिका में कई अर्थाधिकारियां हैं।

इसके बाद, सरमा ने एफआईआर दर्ज कराई और अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। असम पुलिस ने उनके दिल्ली घर पर छापा मारा, लेकिन उस समय वे दिल्ली से बाहर थे।

खेड़ा ने असम की उचित अदालत तक पहुँचने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय में ट्रांजिट अग्रिम जमानत का आवेदन किया। उच्च न्यायालय ने उन्हें अस्थायी राहत दी, जिससे उन्हें सीमित सुरक्षा मिली, और विधिवत जमानत के लिए असम की क्षेत्राधिकार वाली अदालत का रुख करने का निर्देश दिया।

हिमंता सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और तेलंगाना उच्च न्यायालय के ट्रांजिट जमानत आदेश पर स्टेटे डे दिया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के इंतजाम पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि, इस व्यवस्था की निगरानी करने में उनकी क्षमता पर संदेह जताया जा रहा है। लेकिन पहले कदम उठाने की चमक है और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के ध्यान से चूक गए ट्रंप ने अपने तरीके से घोषणा की कि ईरान जहाजों और बंदरगाहों पर अमेरिकन ब्लॉकैड फिलहाल जारी रहेगा। इस प्रकार ट्रंप ने खेल बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाई, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईरान की अचानक घोषणा ने उन्हें चतुराई से मात दे दी।

डॉनल्ड ट्रंप के अस्थिर तरीकों को देखते हुए, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि वह ब्लॉकैड को हटाने या होम्पूज जल में पीछे हटने की घोषणा कब करेगा। ब्लॉकैड की नीति जारी रखने से अमेरिका शेष विश्व, खासकर चीन, को परेशान कर रहा है।

चीन ईरान से तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है और अब इसे असर महसूस हो रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह होगा कि जब ईरानी कच्चे तेल से

ईरान ने अचानक ...

भरा कोई जहाज चीन के बंदरगाह के लिए जाएगा और अमेरिकी ब्लॉकैड से टकराएगा, तो क्या अमेरिकी नौसेना उसे वापस लौटने के लिए बाध्य करेगी या उसे बोर्डिंग और तलाशी के लिए रोक देगी।

संकेत है कि ईरान-अमेरिका शांति वार्ता जल्द ही फिर से शुरू हो सकती है। बेहरत संभावनाओं को देखते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि वे स्वयं पाकिस्तान यात्रा करेंगे, ताकि शांति समझौते को औपचारिक रूप दिया जा सके। लेकिन संकेत है कि युद्ध क्षेत्र में राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।

‘चाणक्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रहे हैं। वे मेरी बात से सहमत हैं। चाणक्य वाले कमेंट पर गृह मंत्री मुस्कुराए और कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी।

महिला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्योंकि ओबीसी और अन्य वर्गों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है, जो अब तक नहीं हुआ।

नीरव मोदी और अमित शाह चूँकि हार गए हैं, इसलिए अब वे यह कथित कहानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है और असम में केवल भाजपा ही महिलाओं की हितैषी है।

तीन दिन का विशेष सत्र भाजपा ने महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए बुलाया था, लेकिन बिल के बहाने सरकार इसे परिसीमन से जोड़ रही है, सौटों को 850 तक बढ़ा रही है और वह भी बिना जमानत के।

परिणाम अपेक्षित था। घटना की दिशा तय हो चुकी है। यह भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के अंत की शुरुआत है।

विपक्ष को तोड़ने के प्रयास विफल रहे और भाजपा के लिए यह आत्ममंथन का समय है, सही और गलत की पहचान करने का समय है।

कर्नाटक के कांग्रेस विधायक को उम्रकैद की सजा

बंगलूरु, 17 अप्रैल। कर्नाटक के भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में सजा की अवधि (क्वॉ